

राजस्थान दिवस कार्यक्रम श्रृंखला- बाड़मेर में राज्यस्तरीय महिला सम्मेलन

मु.मंत्री भजनलाल ने कहा, नारी का सम्मान समाज
और देश-प्रदेश के विकास की पहली सीढ़ी

बाड़मेर/जयपुर, 25 मार्च। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारे देश और प्रदेश का इतिहास वीरता और त्याग से भरा हुआ है। कालीबाई भील, रानी प्रथिनी, मोराबाई, पना धाय और अमृता देवी जैसी महान महिलाओं ने अपनी शक्ति, सामर्थ्य और दृढ़ संकल्प का परिचय देकर अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। शर्मा मंगलवार को बाड़मेर के आदर्श स्टेडियम में राजस्थान दिवस समारोह के तहत आयोजित महिला सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि गौरवशाली सनातन संस्कृति को सम्मान देते हुए, इस बार राजस्थान दिवस अंग्रेजी कलेण्डर के स्थान पर भारतीय पंचांग की तिथि नव संवत्, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा (30 मार्च) को मनाया जा रहा है। इसी दिन सरदार वल्लभभाई पटेल ने रियासतों को मिलाते हुए राजस्थान की स्थापना की थी। इस वर्ष भी रेवती नक्षत्र इंद्रयोग का वही संयोग बन रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति में नारी को नारायणी का दर्जा प्राप्त है। नारी का सम्मान समाज और देश-प्रदेश के विकास की पहली सीढ़ी है, इसीलिए राजस्थान दिवस समारोह का पहला कार्यक्रम हमने मातृशक्ति को समर्पित किया है।

मुख्यमंत्री शर्मा ने महिला सम्मेलन में विभिन्न योजनाओं की चयनित लाभार्थियों से संवाद किया तथा महिला



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान दिवस समारोह के श्रृंखला में बाड़मेर में आयोजित राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने बालिकाओं को 5 हजार स्कूटी वितरित की।

समूहों को लगभग 100 करोड़ रुपये की आजीविका संवर्धन निधि का हस्तान्तरण और 5 हजार महिलाओं को इंडकेशन कुक टॉप का वितरण किया। साथ ही, उन्होंने स्वामी विवेकानन्द स्कॉलरशिप फॉर अकेडमिक एक्सलेंस के अंतर्गत, 164 छात्राओं को चयन पत्र वितरित किए। उन्होंने कहा कि आज 5 हजार स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि का वितरण किया गया है। शर्मा ने कहा कि किशनगढ़

में फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल के माध्यम से प्रदेश की बेटियों को पायलट बनाया जा रहा है।

शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार युवा एवं महिलाओं को सरकारी नौकरियां उपलब्ध कराने की दृष्टि से निरंतर भर्तियां आयोजित कर रही है। इस बजट में भी हमने सवा लाख भर्तियों की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भर्तियों का आयोजन पूर्ण पारदर्शिता के साथ कर

■ मुख्यमंत्री ने बाड़मेर के आदर्श स्टेडियम में राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन को संबोधित किया और महिला कल्याण की विभिन्न योजनाओं में चयनित लाभार्थियों से बात की।

रही है और हमारे एक साल के कार्यकाल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, जबकि पूर्ववर्ती सरकार के समय में एक के बाद एक पेपरलीक हुए और युवाओं के सपनों के साथ विश्वासघात हुआ।

उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजा जा रहा है।

समारोह में पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत, उद्योग राज्यमंत्री के.के. बिश्नोई, विधायक श्रीचंद्र कुपलानी, आदुराम मेघवाल, हमीर सिंह, प्रियंका चौधरी, अरुण चौधरी, छोटसिंह भाटी, प्रतापपुरी, रविन्द्र सिंह भाटी, प्रभारी सचिव सुबीर कुमार, महिला एवं बाल विकास विभाग शासन सचिव डॉ. महेन्द्र सोनी सहित, बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित थीं।

दिल्ली का एक लाख करोड़ रु. का बजट पेश

नयी दिल्ली, 25 मार्च। दिल्ली सरकार ने महिला समृद्धि योजना के लिए राशि आवंटित करने, बसों में महिलाओं को मुफ्त सफर करने की योजना को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए कांड जारी करने, जैसी कई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा करते हुए, मंगलवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए एक लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जिसमें 5100 करोड़ रुपये की राशि महिला समृद्धि योजना के लिए निर्धारित की गयी है।

यह पहला मौका है, जब दिल्ली विधानसभा में एक लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया

■ यह पहला मौका है जब इतना बड़ा बजट पेश हुआ है।

गया है। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू हुआ था और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार ने 27 साल बाद मंगलवार को अपना पहला बजट पेश किया। मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री रेखा गुप्ता जब विधानसभा में बजट पेश करने के लिए खड़ी हुईं, तो भाजपा विधायकों ने मेजें थपथपा कर उनका अभिवादन किया और मोदी-मोदी के नारे लगाए। गुप्ता ने दो घंटा 18 मिनट तक बजट भाषण दिया, जो दिल्ली विधानसभा के इतिहास में अब तक का सबसे लंबा बजट भाषण है।

जस्टिस वर्मा पर लगे आरोपों की जांच शुरु

सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की तीन सदस्यीय
आन्तरिक समिति ने उस कमरे की जांच की जहां
आग लगने के बाद नकदी मिलने की खबर है

नयी दिल्ली, 25 मार्च। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के आवास पर भारी मात्रा में नकदी मिलने के मामले में उच्चतम न्यायालय की ओर से नियुक्त न्यायाधीशों की तीन सदस्यीय आंतरिक समिति ने मंगलवार को जांच शुरू कर दी। सूत्रों ने बताया कि तीनों न्यायाधीश दोपहर करीब एक बजे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में न्यायमूर्ति वर्मा के 30, तुगलक-क्रॉस स्टैंड स्थित आधिकारिक आवास पर पहुंचे। वे करीब 45 मिनट तक न्यायमूर्ति वर्मा के आधिकारिक आवास के अंदर रहे और उन्होंने घटनास्थल का गहन

निरीक्षण किया। समिति के सदस्यों में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी एस संघवालिया और कर्नाटक उच्च न्यायालय की न्यायाधीश अनु शिवरामन शामिल हैं।

सूत्रों ने बताया कि उन सदस्यों ने उस कमरे की जांच की, जहां आग लगने के बाद कथित तौर पर नकदी मिली थी।

हालांकि, न्यायमूर्ति वर्मा ने अपने खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों का जोरदार खंडन किया।

अपने जवाब में उन्होंने पहले दावा किया था कि जिस कमरे में आग लगी थी और जहाँ कथित तौर पर नकदी मिली थी, वह एक आउटहाउस था, न कि मुख्य इमारत, जहाँ न्यायाधीश और उनका परिवार रहता है।

उन्होंने अपने जवाब में कहा, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि मेरे या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा उस स्टोररूम में कभी भी कोई नकदी नहीं रखी गई थी और मैं इस बात की कड़ी निंदा करता हूँ कि कथित नकदी हमारी थी। यह विचार या सुझाव कि यह नकदी हमारे द्वारा रखी या संग्रहित की गई थी, पूरी तरह से बेतुका है।

धनखड़ ने “जुडीशियरी” ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हैं। धनखड़, पिछले कुछ समय में, न्यायपालिका एवं कोलॉजियम व्यवस्था के खिलाफ बोलते आ रहे हैं। यह किसी से छिपा नहीं है कि मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है, तभी से, 2014 से ही, वह स्वतंत्र न्यायपालिका के पर कतरने का हर संभव प्रयास करती आ रही है।

जस्टिस वर्मा के निवास पर कथित रूप से बड़ी मात्रा में करेन्सी नोट मिलने

की दुर्घटनापूर्ण घटना ने कई सवाल खड़े किये हैं, लेकिन इस घटना से सत्तारूढ़ पार्टी को न्यायपालिका पर नियंत्रण रखने के प्रयासों के नवीनीकरण का सुअवसर निश्चित रूप से मिल गया है।

सेवानिवृत्त प्रोफेसर प्रदीप माधुर ने कहा कि न्यायपालिका में उच्चस्तरीय भ्रष्टाचार से किसी को इनकार नहीं है, लेकिन राजनैतिक तंत्र भी, अगर उससे ज्यादा नहीं, तो उससे कम भ्रष्ट नहीं है।

क्या भाजपा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

दोनों दलों के समर्थकों को 2026 में अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद है। अभिनेता विजय के राजनीति में प्रवेश को ध्यान में रखा जाएगा, अभी वे नए हैं और वे किस नुकसान पहुंचाएंगे, यह देखा अभी बाकी है।

वन रक्षक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सारण ने वन रक्षक भर्ती परीक्षा-2020 13 नवम्बर 2022 का सॉल्व्ड पेपर को परीक्षा से पूर्व पढ़ने के लिए अपनी ई-नोवा कार में 7 कैडीट व पेपर हैंडलर को अपने ड्राइवर के साथ बाड़मेर से प्राइवेट बस स्टैंड उदयपुर भेजा था जहां से आरोपित कंचराम जाट वांछित आरोपित जबराम जाट के कहने पर, अभ्यर्थियों ने आरोपित सांवलाराम जाट के किराए के मकान उदयपुर ले गया। सभी कैडीटों को उनकी पारी के अनुसार वन रक्षक भर्ती परीक्षा-2020 का सॉल्व्ड पेपर पढ़ाए गए, जो कंचराम ने दिए थे।

जस्टिस वर्मा के इलाहाबाद हाई कोर्ट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जले होने का वीडियो सामने आया। उसके बाद 20 मार्च को न्यायाधीश वर्मा का स्थानांतरण इलाहाबाद उच्च न्यायालय करने का प्रस्ताव पारित किया गया।

उच्चतम न्यायालय कोलॉजियम द्वारा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा का इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरण के प्रस्ताव के खिलाफ बार एसोसिएशन द्वारा सोमवार को जनरल हाउस (आमसभा) बुलाकर महाभियोग लाने की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया। साथ ही, न्यायाधीश के खिलाफ

प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई जांच कराने का प्रस्ताव पास किया गया। प्रस्ताव को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भेजा जाएगा।

जनरल हाउस में प्रस्ताव पारित किया गया कि बार एसोसिएशन न्यायमूर्ति वर्मा का कहीं भी तबादला करने का विरोध करती है। प्रस्ताव कहता है कि न्यायमूर्ति वर्मा ने जो फैसले इलाहाबाद उच्च न्यायालय या दिल्ली उच्च न्यायालय में सुनाए हैं, उन पर पुनर्विचार किया जाए।

बैठक में यह भी मांग की गई कि जांच

पूरी होने तक न्यायाधीश वर्मा का किसी भी दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण नहीं किया जाए, साथ ही जजों की नियुक्ति में “अंकल जज सिंड्रोम” (भाई भतीजावाद और पक्षपात) खत्म किया जाए, न्यायाधीश के परिवार और रिश्तेदारों से संबंधित न्यायाधीशों का स्थानांतरण दूसरे उच्च न्यायालयों में किया जाए। बैठक में अधिवक्ताओं ने कहा कि ऐसे न्यायाधीशों को न्याय के मंदिर में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। इससे न्याय की पारदर्शिता प्रभावित होती है।

पटवारी भर्ती ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए दोनों को निर्दिष्ट किया गया है। निर्दिष्ट अवधि के दौरान इनका मुख्यालय उपाध्यक्ष अधिकारी कार्यालय, पिंडवाड़ा रहेगा और नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा। अब तक 86 राज्यकर्मियों को सेवा से बर्खास्त किया जा चुका है, जबकि 189 अन्य कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच जारी है। जैसे-जैसे जांच पूरी हो रही है, आरोपी कर्मचारियों को पदों से हटाया जा रहा है।

भाजपा ईद पर देगी सौगात...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कमाल बाबर, बबलु मंसूरी, फहीम सैफी, नईम सैफी, फैसल मंसूरी, सहित बड़ी संख्या में मोर्चे के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद थे।

इस मौके पर मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने संवाददाताओं से कहा कि मोदी के सफल नेतृत्व में भारत सबका साथ सबका विकास और सबका विकास की रणनीति पर आगे बढ़ रहा है।

उन्होंने कहा कि मोर्चे के 32 हजार पदाधिकारी एक मस्जिद से मस्जिद कमेटी के सहयोग से 100 32 हजार मस्जिदों से सम्पर्क कर 32 लाख जरूरतमंदों को “सौगात - ए - मोदी” किट के माध्यम से उपहार स्वरूप जरूरत की चीजें पहुंचाएंगे।

किट में खाद्य सामग्री के अलावा कपड़े, सेवई, खजूर, मेवे और चीनी शामिल होंगे। महिलाओं के लिए किट में सलवार-सूट का कपड़ा होगा, जबकि पुरुषों के लिए कुर्ता-पायजामा शामिल है।

भाजपा का यह अभियान गरीब और जरूरतमंद मुस्लिम परिवारों को सहायता प्रदान करने के साथ-साथ समाज के विभिन्न वर्गों तक अपनी पहुंच बढ़ाने का भी एक प्रयास माना जा रहा है। प्रत्येक पदाधिकारी एक मस्जिद से मस्जिद कमेटी के सहयोग से 100 जरूरतमंद व्यक्तियों को चिह्नित करके उन तक “सौगात - ए - मोदी” किट उपहार स्वरूप पहुंचाने का काम करेंगे।

MARUTI SUZUKI

NEXA

GRAB IT BEFORE THE PRICE HIKE IN APRIL.

DRIVE HOME YOUR FAVOURITE NEXA CAR BEFORE THE PRICES GO UP.

CREATE. INSPIRE.

17th March 2025

Maruti Suzuki India Ltd. to hike car prices by up to 4% from April.

Maruti Suzuki India Ltd. announced on March 17th that it will increase car prices by up to 4% starting from April 2025, citing rising raw material and operational costs. The price hike will vary across different models.

3 years 100 000 km WARRANTY*
EXTENDABLE UPTO 6 YEARS

ONLY 06 DAYS LEFT

CONSUMER OFFERS OF UP TO ₹1 00 000*

EXCHANGE BONUS OF UP TO ₹1 00 000*

PER LAKH EMI STARTING FROM ₹1 470*.

ADDITIONAL SCRAPPAGE BONUS UP TO ₹15 000 IS AVAILABLE AGAINST VALID CERTIFICATE OF DEPOSIT.



SCAN TO CONNECT TO A SHOWROOM NEAR YOU



E-BOOK TODAY @ WWW.NEXAEXPERIENCE.COM

Contact us at 1800-200-6392 1800-102-6392

For detailed T&C kindly visit nearest dealership. Maruti Suzuki India Limited reserves the right to discontinue offers without notice and offers may vary across variants. *Offer includes consumer offer, exchange bonus and institutional or rural offer (wherever applicable) on select models/variants. Finance is at the sole discretion of financier. 3 years or 100 000 km - whichever is earlier. Scrappage offer valid for limited period only and is brought to you by Maruti Suzuki Toyota India Private Limited (a joint venture company between Maruti Suzuki India Ltd and Toyota Tsusho Group). Above offers are valid till 31st March 2025. Black glass shade on the vehicle is due to the lighting effect. Images used are for illustration purposes only. Car color may vary due to printing on paper.

राष्ट्रदूत हिन्दू संयुक्त परिवार की ओर से सोमेश शर्मा द्वारा ज्वाइन्ट मॉडिया, आजाद मार्ग, मेन रोड, आयड, उदयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 57928/93 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स: 0141-2373513 कोटा कार्यालय: पलायथा हाजस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032, फैक्स: 0744-2386033 बीकानेर कार्यालय: कुम्भाना हाऊस, हनुमान हथा, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371 अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स: 0145-2624665 जालौर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालौर। फोन 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डोलसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डोलसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908